महाराष्ट्र के राज्यपाल

माननीय श्री. भगत सिंह कोश्यारी

का

अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मुम्बई में संयुक्त अधिवेशन

०३ मार्च २०२२

सम्मानीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय एवम्
राज्य विधानमंडल के सदस्यगण,

वर्ष २०२२ में राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

२. मेरी सरकार, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जैसे और अन्य महान स्वप्नद्रष्टा एवं समाज सुधारकों द्वारा अधिकथित किये गये उच्च आदर्शों का निरंतर अनुसरण कर रही है।

३. मेरी सरकार, महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी भाषी लोगों के अधिकारों के लिए उनके साथ खड़े रहने के लिए दृढ़ है और १६ दिसम्बर, २०२१ पर बेंगलुरू में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को विद्रुपित करने और बेलगाँव में मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष पर स्याँही फेंकने की घटनाओं की कड़ी भर्त्सना करती है। विवादित सीमावर्ती क्षेत्र के मराठी भाषी लोगों के विरुद्ध कर्नाटक सरकार के कई दमनकारी कृत्य निंदनीय है।

४. राज्य, पिछले दो वर्षों से कोविड़-१९ महामारी का सामना कर रही है। मैं उन लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और इस महामारी से निपटने में मदद करनेवाले सभी स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रसरता से काम करनेवाले कर्मियों की बहादूरी और निःस्वार्थता को प्रणाम करता हूँ।

५. अब तक, महाराष्ट्र ने, कोविड़-१९ संक्रमण की तीन लहरों का सामना किया है। राज्य में दूसरी लहर, पहली लहर की तुलना में अधिक तीव्र थी। मार्च और जून २०२१ के बीच राज्य में करीब ४० लाख नए कोविड़-१९ के रूग्ण देखे गये हैं। इस लहर की चरमसीमा पर, महाराष्ट्र में ६५,००० से अधिक रोजाना नये रूग्ण थे। अधिकतम सक्रिय रूग्ण लगभग ७ लाख थे।

६. मेरी सरकार, अगस्त और सितम्बर २०२० में संक्रमण की प्रथम लहर के पश्चात्, पूरी तरह से तैयार थी। परिणामस्वरूप, जब मार्च से जून २०२१ के बीच राज्य में अगली लहर आई तब ६,५०० सुविधा केन्द्र थे जिनमें से, ४ लाख ५० हजार आइसोलेशन बेड़, ४०,००० आईसीयू बेड़, १ लाख ३५ हजार ऑक्सीजन बेड़ और १५,००० से अधिक वेंटिलेटर उपलब्ध किये गए थे। ६०० से अधिक प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध की हैं।

७. चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता एक अल्पकालिक बाधा थी। उसी समय पर १,७०० मेट्रिक टन की अधिकतम आवश्यकता के मुकाबले महाराष्ट्र प्रतिदिन लगभग १,२५० मेट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा था । प्रतिदिन लगभग ४५० मेट्रिक टन की यह कमी जो लगभग २ सप्ताह के लिए चलती रही वह भारतीय हवाई दल और भारतीय रेल के समन्वयन द्वारा प्रबंधित की गयी थी।

८. मेरी सरकार ने, राज्य की द्रव रूप ऑक्सीजन भंडार क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्णय लिए हैं। अप्रैल और मई २०२१ में तेजी से बढ़ते संक्रमण के दौरान तीन दिनों की अधिकतम माँग के बराबर की भंडार क्षमता का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। अतिरिक्त ५,००० मेट्रिक टन भंडार क्षमता का नियोजन किया गया था जिनमें सें २,७०० मेट्रिक टन की भंडार क्षमता पहले से ही बनाई जा चुकी है।

९. "मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन" के अधीन, मेरी सरकार ने, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कार्यान्वित की है। आज, राज्य में कुल १,८७० करोड़ रुपयों के कुल निवेश के साथ ११४ नवीन ऑक्सीजन उत्पादन परियोजनायें स्थापित की गई हैं। इससे हमारी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता १,४८० मेट्रिक टन से बढ़ेगी और इसमें हम आत्मनिर्भर होंगे।

१०. सम्मानीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशनों के अनुसार, महाराष्ट्र ने १,४०,००० से अधिक मामलों में कोविड़-१९ के कारण मृतकों के परिजनों को प्रति ५०,००० रुपयों की क्षतिपूर्ति अदा की है।

११. जब जनवरी २०२१ में पहली बार कोविड़-१९ के टीके उपलब्ध हुए तब से, महाराष्ट्र, विशिष्ट अवधि के लिए संपूर्ण टीकाकरण हुये व्यक्तियों की सबसे बड़ी संख्या के साथ औषधि मात्रा देनेवालों की कुल संख्या प्रबंधित करनेवाला प्रमुख राज्य है।

१२. अब तक, महाराष्ट्र की प्रौढ़ जनसंख्या के ९१ प्रतिशत लोगों को कोविड़-१९ टीका की कम-से-कम एक औषधि मात्रा मिली है और प्रौढ़ जनसंख्या के ७० प्रतिशत लोग पूरी तरह टीकाकृत हो गए हैं। १५ से १८ वर्ष की आयु समूह में ५७ प्रतिशत से अधिक बच्चों ने टीके की उनकी पहली औषधि मात्रा प्राप्त की है।स्वास्थ्य सेवा देनेवाले कर्मचारी, अग्रणी कोरोना योद्धा और साठ से अधिक आयु के नागरिकों को पूर्वोपात्र टीका (तिसरी मात्रा) देना प्रारंभ हुआ है।

१३. " माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी " यह अभिनव स्वास्थ्य जाँच मुहीम, पिछले वर्ष से कार्यान्वित की गई हैं ।

मेरी सरकार ने, टीकाकरण को अधिक बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव कदम उठाए हैं। दिसम्बर २०२१ में, "हर घर दस्तक" मुहीम कार्यान्वित की गई थी और लगभग ३५,००० गाँवों को और ५५ लाख परिवारों को टीकाकरण दलों ने भेंट दे दी हैं। इस मुहीम के दौरान, १ करोड़ २५ लाख से अधिक प्रथम औषधि मात्रा और २८ लाख से अधिक द्वितीय औषधि मात्रा दी गई थी। २५ अक्तूबर से २ नवम्बर २०२१ के बीच महाविद्यालय जानेवाले युवाओं के लिए मिशन "युवा स्वास्थ्य" कार्यान्वित किया गया था। इस मिशन के अधीन १ लाख ८ हजार से अधिक छात्रों को महाविद्यालय परिसर के भीतर कोविड़-१९ टीके की औषधि मात्रा दी गई थी।

१४. कोविड़-१९ संक्रमण की तीसरी लहर दिसम्बर २०२१ के तीसरे सप्ताह के आसपास शुरू हुई। राज्य की पूर्व नियोजन और टीकाकरण मुहिम में अग्रसक्रीय भूमिका के कारण, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं पर कोई उल्लेखनीय तनाव नहीं आया हैं। हालाँकि, दिसम्बर २०२१ और जनवरी २०२२ के महीने के दौरान राज्य ने, लगभग १० लाख ५० हजार नए कोविड़-१९ रूग्ण दर्ज किए है, परंतु मृत्यु दर ०.१ प्रतिशत से कम रही है।

१५. सभी कोविड़–१९ रुग्णों पर कोविड़-१९ नामनिर्देशित सरकारी अस्पतालों में विनाशुल्क उपचार किये जा रहे है। " महात्मा फुले जीवनदायी योजना " के लिए सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के लिए उचित दर विनियमित किये गये हैं । सरकारी अस्पतालों के अलावा, निजी अस्पतालों में भी कोविड़-१९ के मरीजों के लिए पर्याप्त बेड़ आरक्षित किए गए थे। निजी अस्पतालों में उपचार का खर्च, प्रयोगशाला परीक्षणों, सी.टी. स्कॅन, मास्क आदि के खर्च को लोक हित में विनियमित किया गया था।

१६. " प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना " के अधीन कोविड़-१९ के मरीजों की देखभाल के दौरान अपनी जान गँवानेवाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिवारों को ५० लाख रुपयों की क्षतिपूर्ति दी गई है। अब तक ऐसे १९५ लाभधारियों को क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है और अधिकतर ६४ मामलें विद्यमानतः विचाराधीन है।

१७. मेरी सरकार ने, उन बच्चों को, जिन्होंने कोविड़-१९ महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है, उन्हें एकमुश्त ५ लाख रुपयों की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

१८. कोविड़-१९ महामारी के कारण जो महिला विधवा हो गई थी उन महिलाओं को विद्यमान सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए "वात्सल्य" अभियान शुरू किया है।

१९. मेरी सरकार ने, कोविड़-१९ महामारी के कारण अपने परिवार प्रमुख को खो दिया है, ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों की विधवाओं को आजिविका और रोजगार देने के लिए " वीरभद्रकाली तारारणी स्वयंसिद्धा योजना " शुरू की है।

२०. " कोरोनामुक्त गाँव पुरस्कार योजना " के अधीन महामारी रोकने के लिए बेहतर प्रदर्शन करनेवाली ग्राम पंचायतों को ३० लाख रुपयों से लेकर १ करोड़ रुपयों तक के पुरस्कार दिये जायेंगे।

२१. मेरी सरकार ने, संपूर्ण राज्य के ५६,००० कलाकारों और ८४७ संगठनों को जो महामारी के कारण वित्तीय तनाव का सामना कर रहें थे उन्हे ३५ करोड़ एकमुश्त वित्तीय सहायता दी है।

२२. मेरी सरकार ने, नागपुर में, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर अतिविशेषोपचार चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है। यह १७ स्नातकोत्तर और ११ अतिविशेषोपचार पाठ्यक्रम चलाएगी और इसमें ६१५ बेड़वाला एक अस्पताल भी होगा।

२३. महाराष्ट्र राज्य ने किये, कोविड़-१९ निवारक उपायों की सन्माननीय उच्चतम न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्तर पर सराहना की गई हैं, इस संबंध में मुंबई शहर अन्य शहरों के लिये पथदर्शी शहर बना है ।

२४. मेरे सरकार को, कोविड़-१९ महामारी के कारण आयी आर्थिक मंदी से वित्तीय निर्णय लेना अधिक चुनौतिपूर्ण हो गया था। केंद्र सरकार द्वारा १८ फरवरी २०२२ तक राज्य को देय वस्तु एवं सेवा कर की २९,९४२ करोड़ रुपयों की क्षतिपूर्ति न मिलने के परिणामस्वरूप यह अधिक जटिल हो गया हैं।

२५. तथापि, राज्य सरकार, इस वित्तीय संकट के बावजूद आर्थिक क्रियाकलापों को फिर से शुरू करने, औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और उसी समय में पर्यावरण का संरक्षण करने के लिये पहल करने में कामयाब रही है। राज्य सरकार ने, इस कठिन समय के दौरान, समाज के असुरक्षित घटकों की पीड़ा कम करने का हमेशा प्रयास किया है। राज्य में लोगों को वित्तीय लाभ और खाद्य सुरक्षा का उपबंध करनेवाली योजनाओं पर विशेष बल दिया है।

२६. कोविड़-१९ महामारी के दौरान, आर्थिक मंदी होने पर भी, मेरी सरकार ने, "मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०" के अधीन १ लाख ८९ हजार करोड़ रुपयों का निवेश शामिल होनेवाले तथा ३ लाख ३० हजार नौकरियों का सृजन होनेवाले ९८ निवेशन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

२७. "माझी वसुंधरा अभियान-एक" के अधीन, मेरी सरकार ने, २१ लाख ९४ हजार वृक्षों का वृक्षारोपण किया है और १,६५० नए हरित क्षेत्रों का निर्माण किया है जिसके परिणामस्वरूप, ३ लाख ७१ हजार टन कार्बनडाइ ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होने में मदद हुई है। "माझी वसुंधरा अभियान-दो" को राज्य के स्थानीय निकायों से १२,००० रजिस्ट्रीकरण का उत्कृष्ट प्रतिसाद प्राप्त हुआ है।

२८. विद्यालयीन बच्चों में, वातावरण परिवर्तन पर जागरूकता निर्माण करने के लिए मेरी सरकार, कक्षा १ से ८ वीं तक के लिए पर्यावरण पाठ्यक्रम विकसित कर रही है।

२९. नीति आयोग ने, मेरी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को स्वीकार किया है और उसकी प्रशंसा की है। पिछले वर्ष की तुलना में, इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रीकरण में, १५७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेरी सरकार ने, ७,००० इ-वाहन मालिकों को, उनके वाहनों की लागत में आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया है। इ-वाहन नीति के अधीन प्रमुख उद्योगों से ९,००० करोड़ रुपयों के निवेशन प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिससे करीब १०,००० नौकरियों के सृजन का अनुमान है।

३०. वातावरण परिवर्तन को अनुकूलित बनाने और प्रभाव कम करने के लिए मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता और उप-मुख्यमंत्री की सह-अध्यक्षता के अधीन महाराष्ट्र वातावरण परिवर्तन परिषद की स्थापना की है।

३१. वातावरण परिवर्तन का सामना करने के महाराष्ट्र के प्रयासों को स्वीकार करते हुए मेरी सरकार ने, स्कॉटलंड में २६ वें कॉप परिषद में अंडर २ कोलिशन लीडरशिप पुरस्कार २०२१ के अधीन एक भाग के रूप में, "प्रेरणाप्रद प्रादेशिक नेतृत्व" पुरस्कार जीता है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि महाराष्ट्र एक मात्र भारतीय राज्य है जिसे यह पुरस्कार मिला है।

३२. मेरी सरकार ने, जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करने के लिए "शिवभोजन योजना" शुरू की है। महामारी के दौरान २ करोड़ ७० लाख भोजन थालियाँ निःशुल्क और ३ करोड़ ६८ लाख भोजन थालियाँ ५ रुपयों में दी गयी है। वर्तमान में, राज्य में १,५२६ केंद्र परिचालन में है और फरवरी २०२२ तक ८ करोड़ से अधिक शिवभोजन थालियाँ वितरित की जा चुकी है।

३३. सन् २०२०-२१ मौसम के दौरान, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन २० लाख ३६ हजार मेट्रिक टन धान और अपरिष्कृत अनाज की खरीद की है। सन् २०२०-२१ के खरीप मौसम में, ५० क्विंटल तक धान के लिये प्रति किसान को प्रति क्विंटल ७०० रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई है। इन किसानों के बँक खाते में कुल १,२०० करोड़ रुपये सीधे जमा किए गए हैं।

३४. मेरी सरकार ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन लगभग १ करोड़ २५ लाख क्विंटल कपास की खरीद की है और लगभग ५ लाख किसानों को ७,०९७ करोड़ रुपये प्रदान किये है। उसी प्रकार, १ लाख ३४ हजार किसानों से १,१४८ करोड़ रुपये का २३ लाख ५२ हजार क्विंटल चना खरीदा है। समग्रतः मेरी सरकार ने, पिछले वर्ष किसानों को ९,४४५ करोड़ रुपये से अधिक रक़म प्रदान की है।

३५. मेरी सरकार ने, "मनोधैर्य" योजना के अधीन अत्याचार और ॲसिड हमले से पीड़ित महिला और बालिकाओं को १० लाख रुपयों तक की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

३६. मेरी सरकार ने, महामारी से अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा और रोजगार में एक प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है।

३७. रत्नागिरी, रायगड़ और अन्य क्षेत्रों में तौक्ते चक्रवात के कारण भारी बाढ़ से राज्य ने, कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इससे ४६१ लोगों की मृत्यु हुई है और ७,३६० करोड़ रुपयों से अधिक मूल्य की सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त हो गई है। मेरी सरकार ने, उसे तत्काल और प्रभावी प्रतिसाद दिया था और राज्य आपदा प्रतिसाद निधि से १५,००० करोड़ रुपये और राज्य बज़ट से अतिरिक्त ५,५०० करोड़ रुपयें उपलब्ध कर दिये थे।

३८. मेरी सरकार ने, कोकण क्षेत्र में भविष्य में आनेवाली प्राकृतिक आपदा से बचाव करने के लिए मूलभूत सुविधा निर्माण करने के लिए ३,२०० करोड़ रुपयों के पैकेज को भी मंजूरी दी है।

३९. मेरी सरकार ने, सूक्ष्म सिंचाई इकाईयों को स्थापित करनेवाले किसानों को " शाश्वत कृषि सिंचन योजना " के अधीन उच्चतम आर्थिक सहायता के रूप में २०० करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

४०. मेरी सरकार ने, किसानों के जैविक कृषि उत्पादों के प्रमाणिकरण के लिए अकोला में महाराष्ट्र जैविक प्रमाणिकरण अभिकरण की स्थापना की है।

४१. मेरी सरकार ने, " आज़ादी का अमृत महोत्सव " मनाने के लिये ५०० करोड़ रुपये मंजूर किये है। मेरी सरकार ने, " आज़ादी का अमृत महोत्सव " के अधीन ग्राम पंचायत स्तर पर देश में सबसे अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

४२. " आज़ादी का अमृत महोत्सव " के अवसर पर केंद्र सरकार ने, २० से २५ दिसम्बर २०२१ तक सुशासन सप्ताह मनाया। यह प्रशंसनीय बात है कि, केंद्र सरकार के सुशासन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, सन् २०१९-२० और सन् २०२०-२१ में मेरी सरकार का देश में दूसरा क्रमांक आया है।

४३. मेरी सरकार ने, जिसके लिए आशियाई विकास बैंक के ज़रिये अर्थसहायता प्राप्त ५,००० करोड़ रुपयों की परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अधीन करीबन १,००० किलोमीटर सड़के उन्नयित और कॉंक्रिटीकृत की गई है। परियोजना का दूसरा चरण भी अनुमोदित किया गया है जिसके अधीन १०,००० करोड़ रुपये लागत पर २,००० किलोमीटर सड़क उन्नयित की जायेगी।

४४. हायब्रीड ॲन्युईटी योजना, ८,६५४ किलोमीटर सड़क के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही है। हायब्रीड ॲन्युईटी योजना के अधीन कुल १३८ पॅकेज बनाए गए है और ३,६७५ किलोमीटर सड़कों का संनिर्माण पूरा हो चूका है।

४५. मेरी सरकार ने, " हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग " के ७०१ किलोमीटर लंबाई का ७७ प्रतिशत संनिर्माण कार्य पूरा किया है। मेरी सरकार ने, इस महामार्ग को नागपुर से गोंदिया एवं गढ़चिरोली से नागपुर तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।

४६. मेरी सरकार ने, रायगड़ जिले के रेवस से सिंधुदूर्ग जिले के रेड़ी तक तटीय महामार्ग के चार लेन और कंक्रीटीकरण करने का कार्य भी हाथ में लिया है।

४७. मेरी सरकार ने, मुंबई में समुद्री तटीय मार्ग परियोजना का ५० प्रतिशत कार्य पूरा किया है और यह महत्त्वाकांक्षी परियोजना मुंबई में यातायात जलद गति से और कारगर बनाने में मदद करेगी।

४८. मेरी सरकार ने, पुणे शहर के रिंग रोड़ हेतु भूमि अर्जन का कार्य हाथ में लिया है।

४९. कोविड-१९ महामारी के कारण विद्यालय प्रत्यक्ष रुप से शुरू न होने के बावजूद मेरी सरकार ने, " माझे विद्यार्थी, माझी जबाबदारी " और " अभ्यासमाला पहल " के अधीन विद्यार्थियों की शिक्षा निरंतर जारी रखी है। कक्षा १ से १२ वीं के लिए दिक्षा ॲप के ज़रिए नियमित आधार पर विषयवार सामग्री प्रसारित की है। वर्ष २०२०-२१ में दिक्षा ॲप का उपयोग करने में महाराष्ट्र राज्य, देश में प्रथम स्थान पर रहा है।

५०. " समग्र शिक्षा अभियान " के अधीन मेरी सरकार ने, कक्षा १ से ८ वीं के छात्रों को विद्यालय शुरू होने के पूर्व ही उनके घर पर पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया है। सभी विद्यालयों में द्विभाषा पाठ्यपुस्तकें शुरू की है।

५१. ४८८ स्थानीय प्राधिकरणों के विद्यालयों का राज्य के आदर्श विद्यालयों के रूप में विकास किया जा रहा है।

५२. मेरी सरकार ने, अनुसंधान क्षमता में सुधार लाने के लिए राज्य के छह विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए केंद्रों की स्थापना की है। राज्य में, तीन समूह विश्वविद्यालय, दो नए आदर्श उपाधि महाविद्यालय और एक नवीन सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा हैं।

५३. मेरी सरकार ने, वन अधिकार अधिनियम, २००६ का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। अब तक १,८२,४८३ हेक्टर भूमि आच्छादित करनेवाले १,९२,८४५ व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावों के साथ ही साथ १२,७३,७९७ हेक्टर भूमि आच्छादित करनेवाले ८,२२० समुदाय वन अधिकारों के दावें अनुमोदित किये गये है।

५४. मेरी सरकार ने, उच्चतर शिक्षा लेनेवाले अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ़्त छात्रावास सुविधा प्राप्त करने के लिये उनके परिवारों की वार्षिक आय सीमा २ लाख ५० हजार से ८ लाख रुपयों तक बढ़ाई है। मेरी सरकार ने, पुलिस सिपाही की भर्ती के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों के लिए भर्ती-पूर्व निवासी प्रशिक्षण योजना भी शुरू की है।

५५. मेरी सरकार ने, डिजीटल हस्ताक्षरित सातबारा की हार्ड कॉपी मुफ़्त में वितरित करने का निर्णय लिया है।

५६. मेरी सरकार ने, राज्य में १५ अगस्त से ' ई-पीक पहाणी ' परियोजना का प्रारंभ किया है और अब तक ९५ लाख से अधिक किसानों के मोबाईल ॲप के ज़रिए फसल का निरीक्षण करने के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रीकरण किया है।

५७. मेरी सरकार ने, रोजगार गारंटी योजना से संबंधित फलोद्यान योजना के अनुसार " माँग पर खेत तालाब " के अधीन लगभग १ लाख ५० हजार खेत तालाबों का निर्माण कार्य पूरा किया है। निसर्ग चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त पेड़-पौधों के नवीकरण के लिए ५० करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।

५८. मेरी सरकार ने, धनगर समुदाय के विकास के लिए १३ योजनाओं को मंजूरी दी है। इस वर्ष में ५,३०० धनगर समाज के छात्रों को प्रतिष्ठित अंग्रेजी निवासी विद्यालयों में प्रवेश दिया गया है।

५९. मेरी सरकार ने, प्रत्येक वर्ष १ जनवरी को कोरेगांव-भिमा पर " शौर्य दिन " मनाने का निर्णय लिया है।

६०. मेरी सरकार ने, मुंबई में वरली, ना. म. जोशी मार्ग और नायगाँव के बी.डी.डी. चाल के पुनर्विकास का कार्य हाथ में लिया है। लगभग १५,५०० किरायेदारों को जो बी.डी.डी. चाल में रहते हैं उन्हें ५०० वर्ग फीट क्षेत्र के मकान आबंटित किये जायेंगे।

६१. मेरी सरकार ने, राज्य के ३९१ शहरों में, "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" कार्यान्वित की है। योजना के अधीन १५ लाख ३८ हजार आवासीय यूनिटों को मंजूर किया गया है। अब तक मेरी सरकार ने, योजना के लिये राज्य के हिस्से के रूप में १,७३९ करोड़ रुपये दिये गये है।

६२. मेरी सरकार ने, बृहन्मुंबई नगर निगम क्षेत्र में के ५०० वर्ग फीट तक चटाई क्षेत्रवाले निवासी फ़्लैटों पर संपत्ति कर से छूट देने का निर्णय लिया है।

६३. मेरी सरकार ने, राज्य में एकीकृत विकास नियंत्रण और प्रोत्साहन विनियमन कार्यान्वित किया है और इससे राज्य के नागरिकों को मकान निर्माण की अनुमति प्राप्त करना सुलभ होगा।

६४. यह कहते हुये मुझे खुशी हो रही है कि, नागरी स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान २०२१ में महाराष्ट्र राज्य दूसरे क्रमांक पर है।

६५. मेरी सरकार ने, "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" के अधीन ९ परियोजनाओं को पूरा किया गया और २ लाख ६४ हजार हेक्टर सिंचाई क्षमता को सृजित किया गया है। " बलिराजा जलसंजीवनी योजना " के अधीन १९ परियोजनाओं को पूरा किया है जिससे ३ लाख ७७ हजार हेक्टर सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।

६६. मेरी सरकार ने, २,६३६ मेगा वॅट कुल स्थापित क्षमता की ३४ जलविद्युत परियोजनाओं और १६० मेगा वॅट कुल स्थापित क्षमता से निजीकरण के ज़रिए ३९ छोटी जलविद्युत परियोजनाओं को शुरू किया गया है।

६७. "जल जीवन मुहिम" के अधीन मेरी सरकार ने, ग्रामीण क्षेत्रों में ९७ लाख ५८ हजार घरेलू नल जुड़ाई की है।

६८. मेरी सरकार ने, पुणे-नासिक सेमी-हाय स्पीड रेल परियोजना के लिये वित्तीय भागीदारी को मंजूरी दी है।

६९. कोविड़-१९ महामारी की दूसरी लहर के दौरान, प्रत्येक ऑटोरिक्षा चालक को १,५०० रुपयों की वित्तीय सहायता दी गई है।

७०. पिछले सत्र में, राज्य विधानमंडल ने, शक्ति विधेयक पारित किया है जिसमें महिला और बालकों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम करने के लिये कठोर शिक्षा का उपबंध और ऐसे अपराधों का शीघ्र अन्वेषण और शीघ्र जाँच करने का उपबंध किया है।

७१. मेरी सरकार ने, वडगांव-मावल में एक जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय और सिविल न्यायालय, (वरिष्ठ प्रभाग) और अलिबाग में एक परिवार न्यायालय की स्थापना की है।

७२. मेरी सरकार ने, सभी सरकारी विभागों में मराठी के उपयोग को अनिवार्य करने के लिये महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया है। मराठी भाषा से संबंधित कार्यों की निगरानी करने के लिये एक राज्य स्तरीय समिति और कई जिला स्तर समितियों की स्थापना की गई है।

सम्मानीय सदस्यों, इस सत्र में, नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव, विनियोग विधेयकों, और अन्य विधि विधान आपके विचारार्थ रखे जायेंगे। मुझे यह विश्वास है कि, सम्मानीय सदस्य सम्मिलित होंगे और महाराष्ट्र को अधिक समृद्धि की ओर ले जानेवाले इन प्रस्तावों पर अपने उचित विचार-विमर्शों को प्रदर्शित करेंगे।

मैं दुबारा एक बार, आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !